पहली समिति विकास दर और निवेश बढ़ाने पर काम करेगी, दूसरी रोजगार और कौशल विकास पर। इन उद्देश्यों के लिए कैबिनेट समितियों का गठन संभवत: पहली बार ही किया गया है। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के उत्तरार्ध में इकॉनमी सुस्त पड़ी और समय बीतने के साथ यह रुझान बढ़ता ही गया। बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट मात्र 5.8 फीसदी रही, जिसका असर पूरे वित्त वर्ष की विकास दर पर पड़ा है।

संपादकीय

E-mail: jantaserishta@gmail.com

रफ्तार के लिए

रिजर्व बैंक और आर्थिक विशेषज्ञ शुरू से ही कहते रहे हैं कि निवेश, कारोबार, रोजगार आदि के मामलों को मौद्रिक नीति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इन्हें बढ़ाने का जिम्मा सरकार को ही लेना होगा। रिजर्व बैंक ने विपरीत परिस्थितियों में लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती सरकार की तत्परता को देखकर ही की है। भारतीय रिजर्व बैंक का लगातार तीसरी बार चौथाई फीसदी ब्याज दरें घटाना एक पैकेज के हिस्से की तरह आया है। अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना एनडीए सरकार-2 के अजेंडे में सबसे ऊपर है। पिछले दो-तीन वर्षों में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बुधवार को दो कैबिनेट समितियों का गठन किया गया, जिनके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होंगे। पहली समिति विकास दर और निवेश बढ़ाने पर काम करेगी, दूसरी रोजगार और कौशल विकास पर। इन उद्देश्यों के लिए कैबिनेट समितियों का गठन संभवत: पहली बार ही किया गया है। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के उत्तरार्ध में इकॉनमी सुस्त पड़ी और समय बीतने के साथ यह रुझान बढ़ता ही गया। बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट मात्र 5.8 फीसदी रही, जिसका असर पूरे वित्त वर्ष की विकास दर पर पड़ा है। 7.2 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले अंतत: यह 6.8 प्रतिशत ही रही, जो पांच वर्षों में सबसे कम है। बेरोजगारी की स्थिति चिंताजनक है। चुनाव में मोदी सरकार को इसके लिए विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ी थी। मंत्रिमंडल गठन के दूसरे ही दिन श्रम मंत्रालय द्वारा जारी बेरोजगारी के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत रही, जो 45 साल में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की जनवरी में लीक हुई रिपोर्ट में भी बताया गया था लेकिन तब नीति आयोग ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में ऋणात्मक 0.1 प्रतिशत हो गई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर भी गिरकर 3.1 प्रतिशत पर आ गई। जाहिर है, चुनौतियां काफी बड़ी हैं। प्रधानमंत्री की अगुआई में इन दोनों समितियों को प्रो-एक्टिव होकर कई सारे छोटे-बड़े फैसले करने होंगे। रिजर्व बैंक और आर्थिक विशेषज्ञ शुरू से ही कहते रहे हैं कि निवेश, कारोबार, रोजगार आदि के मामलों को मौद्रिक नीति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इन्हें बढ़ाने का जिम्मा सरकार को ही लेना होगा। रिजर्व बैंक ने विपरीत परिस्थितियों में लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती सरकार की तत्परता को देखकर ही की है। यह फैसला उसने ऐसे समय में किया है जब बाजार में सस्ते कर्ज की मौजूदगी कुछ बड़ी समस्याओं की वजह भी बन सकती है।

टीम मोदी को अब जमीनी स्तर पर 'बेहतर कारगुजारी' दिखानी होगी

लेख -हरि जयसिंह

पहला, निर्मला सीतारमण के भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त एवं कार्पोरेट मामलों की मंत्री के तौर पर उच्च पद सम्भालने के कुछ ही घंटों के भीतर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) गत वर्ष के इसी समय 8.1 प्रतिशत के मुकाबले कम होकर 5.8 प्रतिशत पर आ गया। यह गत 20 तिमाहियों के दौरान सबसे कम विकास दर है। इसने लगभग 2 वर्षों बाद भारत को चीन के पीछे ला खड़ा किया है। जी.डी.पी. के नवीनतम आंकड़े निर्मला सीतारमण के सामने बड़ी चुनौतियों को रेखांकित करते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विश्वास हासिल है। एक चतुर रणनीतिज्ञ सीतारमण ने बड़ी तेजी से शासन की कला सीख ली, प्रशासन तथा राजनीतिक, दोनों मामलों में।

मैं यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कारगुजारी बारे बात नहीं करना चाहता। 2019 के चुनावों में दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी शानदार राजनीतिक कारगुजारी के परिप्रेक्ष्य में आज यह प्रासंगिक नहीं है। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) के जिन बहुत से लोगों से मैं मिला, उन्हें ऐसी जोरदार जीत की कभी आशा नहीं थी। इस कड़े तथ्य की रोशनी में अन्य सब कुछ अप्रासंगिक हो जाता है।

यद्यपि एक जनहितैषी पत्रकार होने के नाते मैं जमीनी हकीकतों बारे चर्चा करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं ताकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी सफलता के नशे में न बह जाएं। अत: सामाजिक हकीकतों को एक ओर रखते हुए मैं विभिन्न अनुभागों पर नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों की याद दिलाऊंगा।

पहला, निर्मला सीतारमण के भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त एवं कार्पोरेट मामलों की मंत्री के तौर पर उच्च पद सम्भालने के कुछ ही घंटों के भीतर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) गत वर्ष के इसी समय 8.1 प्रतिशत के मुकाबले कम होकर 5.8 प्रतिशत पर आ गया। यह गत 20 तिमाहियों के दौरान सबसे कम विकास दर है। इसने लगभग 2 वर्षों बाद भारत को चीन के पीछे ला खड़ा किया है।

जी.डी.पी. के आंकड़े : जी.डी.पी. के नवीनतम आंकड़े निर्मला सीतारमण के सामने बड़ी चुनौतियों को रेखांकित करते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विश्वास हासिल है। एक चतुर रणनीतिज्ञ सीतारमण ने बड़ी तेजी से शासन की कला सीख ली, प्रशासन तथा राजनीतिक, दोनों मामलों में। अब उन्हें जरूरत है अपने वित्तीय कौशल को मजबूत करने की। मुझे विश्वास है कि वह तेजी से सीखने वाली हैं। मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर पहले कार्यकाल के दौरान वह पेचीदा रक्षा मंत्रालय सम्भाल कर पहले ही अपनी मजबूती दिखा चुकी हैं।

दूसरा, कार्यबल के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नजर डालते हैं तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन.एस.ओ.) के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत थी। बेरोजगारी की यह दर पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए ऊंची है। कार्यबल संबंधित यह सर्वेक्षण किन कारणों से पहले जारी नहीं किया गया था, यह हम अब समझ सकते हैं।

भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् कहते हैं, 'यह एक नई बनावट तथा नया सांचा है। इसकी अतीत के साथ तुलना करना अनुचित होगा। मैं 45 वर्षों के दौरान उच्च या निम्न का दावा नहीं करना चाहता।' उन्होंने कहा कि वह इस मामले को यहां महज इसलिए छोडऩा चाहते हैं क्योंकि यह पहले ही विवाद की स्थिति में पहुंच गया है। जो भी हो, नौकरियों संबंधी आंकड़े प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के सामने नीति से संबंधित चुनौती खड़ी करते हैं। निश्चित तौर पर बेरोजगारी के परिदृश्य के लिए कई पहलू है और आंकड़ों संबंधी कोई भी इकलौता स्रोत अपने आप में पूर्ण नहीं है। यह अपने आप में नहीं, सरकार के लिए एक बड़ा कार्य होने वाला है।

मोदी के मंत्र : प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले के दो मंत्रों में एक और मंत्र शामिल कर लिया। उन्होंने अपने पहले के दो मंत्रों 'सबका साथ, सबका विकास' में 'सबका विश्वास' शामिल कर लिया। मैं इन मंत्रों का स्वागत करता हूं। यद्यपि इन मंत्रों को कार्ययोजना में परिभाषित करते हुए जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाने की जरूरत है। यह प्रधानमंत्री का काम है कि वह इन मंत्रों को जमीनी हकीकतों में बदलने के लिए कार्ययोजना बनाएं। क्या मोदी यह करेंगे? यह प्रधानमंत्री तथा उनकी हाईप्रोफाइल टीम के लिए सम्भव होना चाहिए। उन्हें इस बार जमीनी स्तर पर बेहतर कारगुजारी दिखानी होगी। इन कार्यों के लिए मंत्रियों से चुनौतियों की प्रकृति तथा कार्य की प्राथमिकताओं पर केन्द्रित होने की आशा की जाती है। इस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक सुधारवादी मार्ग अपनाना होगा लेकिन अत्यंत सतर्कता के साथ।

चूंकि उत्पादकता एक महत्वपूर्ण कारक है, आऊटपुट बढ़ाने के लिए कौशल विकास, सार्वजनिक अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ-साथ पूंजी गतिशीलता की मदद से समन्वित प्रयासों की जरूरत होगी। इतना ही महत्वपूर्ण होगा ऊर्जा उत्पादन। संक्षेप में, सारा दबाव आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण के साथ-साथ खराब ऋणों से सेफ्टी नैटवर्क सुनिश्चित करने पर होगा। इसके लिए वित्तीय क्षेत्र में जोरदार सुधार जरूरी है, विशेषकर बैंकिंग आप्रेशन्स में। बदले में इसे जरूरत होगी पारदर्शिता तथा जवाबदेही की एक मजबूत प्रणाली की। प्रधानमंत्री को विकेन्द्रीकरण पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। सत्ता के सभी तार प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) में इकट्ठे करना ठीक नहीं है, जो आमतौर पर बदलती जमीनी हकीकतों के सम्पर्क में नहीं होता। इसके साथ ही कृषि, जलवायु परिवर्तन तथा गुणवत्तापूर्ण बीजों, कीमतों व मार्गदर्शन को लेकर किसानों की दुविधा जैसे महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी नीति निर्णय एक ऐसा कार्य है जिसे इस क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों के लिए छोड़ देना चाहिए, जिनसे किसानों की जरूरतों के साथ तालमेल बनाकर समन्वित तरीके से परफार्म करने की आशा की जाती है। यह प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल से सीखने का सही सबक है ताकि विमुद्रीकरण तथा जी.एस.टी. के मामले से ढीले-ढाले रवैए के साथ निपटने जैसी गलतियां न दोहराई जाएं। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है यदि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति ग्रामीण जमीनी हकीकतों को समझना सीख लें और नीति निर्णय लेने से पूर्व सोचें व उस पर उचित प्रतिक्रिया दें। देश को अधपके राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ एक खालीपन की स्थिति में नहीं चलाया जा सकता। हमें देश की पेचीदा आर्थिक चुनौतियों से व्यावसायिक तरीके से निपटने की जरूरत है न कि भगवा रंग के 'विशेषज्ञों' से।

जन-मंच

गिरता भूजल स्तर

जिस प्रकार साल-दर-साल वर्षा में कमी आ रही है, उसी प्रकार भूजल स्तर में भी कमी आ रही है। भारत के अनेक राज्य पानी की कमी के चलते बेहाल हैं, उनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और बिहार में पेयजल के लिए लोग बेहाल हैं। यहां कई कुएं सूख चुके हैं, नदियां, तालाब और पानी के अन्य स्रोत जमींदोज हो चुके हैं। बड़े शहरों और महानगरों में जिस प्रकार भूजल दोहन हो रहा है, जिस तरह से जल बर्बाद किया जा रहा है, उससे तो इन शहरों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। कुछ अधिक सम्पन्न लोग अधिक जल बर्बाद करते देखे जा रहे हैं। जमीन से 500 फीट से भी नीचे से पम्प द्वारा पानी निकालकर घरों और गाड़ियों को धोया जा रहा है तथा बेतहाशा पानी बहाया जा रहा है। कुछ अधिक दबाव पड़ने पर कार्रवाई के नाम पर सौ-पांच सौ रुपये का चालान थमाकर इतिश्री समझी जा रही है, लेकिन प्यासे लोग तो हाहाकार कर रहे हैं। मवेशी प्यास से मर रहे हैं, पर उनको इससे क्या? .

-**सतप्रकाश सनोठिया,** बिलासपुर

हाईटेक हों स्कूल

एक रिपोर्ट के अनुसार, केरल राज्य की सभी सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाया जा चुका है। इसके साथ ही सरकार ने करीब 141 स्कूलों को विश्वस्तरीय बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन दुर्भाग्यवश देश में आज भी कई सरकारी व निजी संस्थान हैं, जो इतने हाईटेक नहीं हैं। आखिर क्यों? कई राज्यों में केवल कागजों पर बच्चों का भविष्य लिखा जा रहा है। सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत और हर मुमकिन कदम उठाने पड़ेंगे, तब कहीं हम उच्चस्तरीय शिक्षा की बात कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में सबसे पहले सुविधाओं और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके बाद ही सभी सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाए जाने पर जोर देना चाहिए। शिक्षा सभ्य समाज का सबसे बड़ा गुरुमंत्र है, सरकार को इस ओर खुली आंखों से देखना चाहिए। .

-**विभाष ए जैन,** अंबिकापुर

चीन के खिलाफ प्रदर्शन

गत रविवार को हांगकांग में 10 लाख लोगों ने चीन के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। 1 जुलाई 1997 के बाद से, जब से चीन के हाथों में हांगकांग की कमान आई है, इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था। जब तक यह ब्रिटेन का उपनिवेश था, यहां का शासन-प्रशासन पूंजीवादी लोकतंत्र की नीतियों से चल रहा था। लोग और समाज उसी संस्कृति में ढल गए थे। हस्तांतरण के समय चीन और ब्रिटेन में यह समझौता लिखित में हुआ था कि हांगकांग के मामले में चीन एक देश दो नीति के तहत काम करेगा। वर्ष 2047 तक उसे इस नियम से बंधे रहना था, लेकिन 2019 में ही चीन ने हांगकांग के लिए नई प्रत्यर्पण नीति का एलान कर दिया, जिसके तहत आरोपियों को चीन प्रत्यर्पित करके मुकदमा चलाया जा सकेगा। यह एक दमनकारी अधिनायकवादी नीति है, जिसे हांगकांग पर थोपा जा रहा है। ब्रिटेन और राष्ट्र संघ को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। .

-**जंग बहादुर सिंह,** भिलाई

शिक्षकों को प्रशिक्षित करें

साक्षरता दर किसी भी देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होती है, पर क्या हमारा मकसद सिर्फ साक्षरता दर बढ़ाना है या सही मायने में बच्चों को शिक्षित करना है। बच्चों के संपूर्ण बौद्धिक विकास और उनकी तर्क शक्ति विकसित करने के लिए एक शिक्षक से अच्छा कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता, अत: यह बात भी काफी आवश्यक है कि शिक्षकों को भी समय-समय पर एक दिशा-निर्देश दिया जाना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई को वास्तविक रूप से सार्थक कैसे बनाया जाए? शिक्षकों को ऐसी व्यवस्था जरूर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे नई शिक्षण पद्धतियों को सीख सकें और बदलते वक्त के साथ बच्चों को कदम से कदम मिलाकर चलने की शक्ति दे सकें। .

-**विवेक कुमार,** महासमुंद

पिछड़े प्रदेशों की पीड़ा

भारत को आजाद हुए सात दशक हो चुके हैं, मगर देश में अब भी कई राज्य ऐसे हैं, जो सदियों से विकास की एक धारा के लिए प्यासे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर सत्तापक्ष फिर से कुरसी पर काबिज होने और विपक्ष इसकी काट के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन कोई भी दल पिछड़े राज्यों को आगे लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, न ही कोई इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाह रहा है। पिछड़े राज्यों का नाम सुनते ही सबसे पहले बिहार का नाम जुबान पर आता है। वहां भले ही विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं होती, जिसका समाधान न हो। बिहार के नौजवान देश भर के बड़े-बड़े प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कोई भी बिहार में रोजगार के नए अवसर के बारे में नहीं सोच रहा है। जाहिर है, गौतम बुद्ध और महावीर की इस भूमि में रोजगार के तमाम अवसर पैदा करने की जरूरत है, तभी इस राज्य का विकास हो पाएगा।.

-**रोशन कुमार,** भिलाई

चिंतन कण
अपनी खुशी

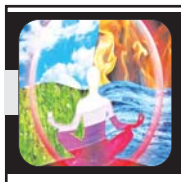

यदि हम भीतर से खुश रहने के लिए तैयार हैं तो फिर हमारा हर काम अपने आप में अनूठा होगा, आनंददायी होगा।

भीतर की अपनी खुशी, अपनी संतुष्टि ही नैसर्गिक खुशी होती है। इसकी तैयारी भीतर से ही करनी होती है। इस खुशी के रहते हुए कोई बाहर का तत्व हमें दुखी नहीं बना सकता। भीतर की जो वास्तविक खुशी है वह कुएं के पानी के उस अनवरत स्रोत की तरह है जो जमीन के अंदर से आता है। कुएं के पानी की तरह अंदर से निकला खुशी का निर्मल झरना आत्मा, हमारे तन-मन और समूचे जीवन को आनंदित कर देता है। निरंतर बहने वाले इस खुशी के स्रोत को अगर कोई रोकता है तो वह हैं-हमारे मन में बसे सक्रिय दुर्गुण और वासनाएं। हम बाहर से कितने ही अच्छे काम कर लें, लेकिन अगर भीतर से खुश रहने के लिए तैयार नहीं हैं तो अच्छे से अच्छा काम भी यंत्र-वत बनकर रह जाएगा। यदि हम भीतर से खुश रहने के लिए तैयार हैं तो फिर हमारा हर काम अपने आप में अनूठा होगा, आनंददायी होगा।

बाहरी खुशी ऊपर रखी टंकी का वह पानी है जो रोज भरा जाता है और रोज टंकी खाली हो जाती है। टंकी में डाला गया पानी इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले सांसारिक भोग-विलास हैं। इंद्रियां इन्हीं बाहरी पदार्थों से सुख चाहती हैं, लेकिन बाहरी पदार्थ से कभी वास्तविक खुशी न किसी को मिली है न मिलेगी। इन्हें तो रोज भरना खाली होते रहना है। अपनी खुशी दूसरों में खोजने वाले लंबे समय तक जीवन-यात्रा नहीं कर पाते हैं, लेकिन संसार में रहना है तो दूसरों के बिना जीवन कट भी नहीं सकता। सुख मिले या दुख, संबंध तो निभाने पड़ते ही हैं। एक बार अगर हमने अपने भीतर की खुशी को जान लिया है तो खुशी हमारी मुट्ठी में है। हम सभी चाहते हैं कि कैसे भी, किसी भी प्रकार से खुशी मिल जाए। विभिन्न प्रकार के वर्कशॉप, आयोजन, महोत्सव किए जाते हैं, लेकिन खुशी कोई आयातित बाहरी पदार्थ नहीं है। यह तो हमारी मानसिक अवस्था है, हमारी सोच की दिशा है। यही दिशा जब सकारात्मक होती है तो खुशी में बदल जाती है। बाहर से प्राप्त खुशी वास्तविक न होकर अस्थाई रूप से प्राप्त खुशी की प्रतिछाया होगी।

-**जज (सेवानिवृत्त) डॉ. निर्मल जैन**

मुरम्मतों का मौसम

एक लंबा अरसा, कहिए पाँच वर्षीय योजना के बाद, कल शाम उन्होंने मुझे रोककर, हाथ जोड़ कर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और बोले, अभी भी हम से नाराज़ हैं बंधुवर। थोड़ी हैरानी हुई कि वे ऐसा क्यूँ कर रहे हैं। उनसे न कोई राज़गी थी न नाराज़गी। हमने भी हाथ जोड़कर ही कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले ही क्षण समझ में आया कि राजनीति के खेत में चुनाव की उपजाऊ फसल रोपने का मौसम आ गया है।

अवसर मिले तो अपने खराब सम्बन्धों को ठीक करते रहना चाहिए। अंजान लोगों से भी संबंध उगाने के प्रयास करने चाहिए। अपने सपने सच करने के लिए एक चींटी की तरह लगे रहना चाहिए, एक न एक दिन तो सफलता मिलती ही है।

एक लंबा अरसा, कहिए पाँच वर्षीय योजना के बाद, कल शाम उन्होंने मुझे रोककर, हाथ जोड़ कर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और बोले, अभी भी हम से नाराज़ हैं बंधुवर। थोड़ी हैरानी हुई कि वे ऐसा क्यूँ कर रहे हैं। उनसे न कोई राज़गी थी न नाराज़गी। हमने भी हाथ जोड़कर ही कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले ही क्षण समझ में आया कि राजनीति के खेत में चुनाव की उपजाऊ फसल रोपने का मौसम आ गया है तभी तो सम्बन्धों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक मुरम्मत ज़ोर शोर से शुरू हो गई है। अब तो किसी भी स्तर के राजनीतिज्ञ से नाराज़गी रखने का वक़्त नहीं रहा। याद आया कई बरस पहले हमने उनकी एक हरकत पर टिप्पणी कर दी थी। हमारी पत्नी ने हमें समझाया भी था कि कहीं यह 'सज्जन' चुने गए तो आपकी खैर नहीं। लेकिन वह कई पार्टियां बदलने के बावजूद हमेशा हारते ही रहे और हम भी बचे रहे। उनके एक बार मुझसे पुन: संबंध नवीनीकरण करने के प्रयास से लगा राजनीति एक अध्यापक भी तो है जो हमें पढ़ाती है कि ज़िंदगी में कोई पक्का दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं हुआ करता।

> एक लंबा अरसा, कहिए पाँच वर्षीय योजना के बाद, कल शाम उन्होंने मुझे रोककर, हाथ जोड़ कर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और बोले, अभी भी हम से नाराज़ हैं बंधुवर। थोड़ी हैरानी हुई कि वे ऐसा क्यूँ कर रहे हैं। उनसे न कोई राज़गी थी न नाराज़गी। हमने भी हाथ जोड़कर ही कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले ही क्षण समझ में आया कि राजनीति के खेत में चुनाव की उपजाऊ फसल रोपने का मौसम आ गया है।

अवसर मिले तो अपने खराब सम्बन्धों को ठीक करते रहना चाहिए। अंजान लोगों से भी संबंध उगाने के प्रयास करने चाहिए। अपने सपने सच करने के लिए एक चींटी की तरह लगे रहना चाहिए, एक न एक दिन तो सफलता मिलती ही है। चुनावी मुरम्मत के मौसम में चाहे नेता एक दूसरे के साथ पुश्तैनी दुश्मनों की तरह व्यवहार करें लेकिन बात वे लोकतंत्र को अधिक मजबूत करते हुए, देश को गौरवशाली व शक्तिशाली बनाने की ही करते हैं। यह मौसम होली की तरह होता है जहां सब गले मिल लेते हैं, क्या पता यह गले मिलना कहीं काम आ ही जाए और गले न मिलना कहीं गले ही न पड़ जाए। याद रखना चाहिए कि राजनेता यदि लगा रहे तो सांसद न सही विधायक न सही एक दिन पार्षद तो बन ही जाता है और अपने मकान का निर्माण तो करवा ही लेता है।

खराब सम्बन्धों की मुरम्मत तो वो पहले ही कर चुका होता है। 'घमंड का सिर नीचा' होने का मुहावरा सफल राजनीति में 'घमंड का सिर ऊंचा' हो जाता है। आजकल जब राजनीतिक मुरम्मत के हर सधे हुए कारीगर का बाज़ार गर्म है, घमंड का सिर पुन: नीचे लटका घूमता है। राजनीति ने मानवीय जीवन को बहुत लचीला मुहावरा बना दिया है जिसके असली अर्थ गुम हो गए हैं और निरंतर मुरम्मत मांग रहे हैं।

कटाक्ष

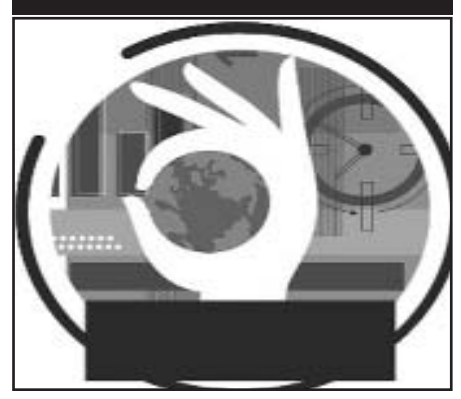

-संतोष उत्सुक

इनकी जुबां

- **ममता बनर्जी**
मुख्यमंत्री

किसी ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है।

तनुश्री दत्ता
अभिनेत्री

Tanushree Dutta ने एक खुला पत्र लिखा हैंद्य जिसमें उन्होंने Aligarh Girl Child Murder Case पर रोष जताया हैं। भारत में महिलाओं के प्रति होनेवाले यौन उत्पीड़न पर भी चिंता जताई है।

पांच सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में 27.5 हजार करोड़ रुपये हुए खर्च।

सुशील मोदी
उप मुख्यमंत्री